

अनुलग्नक क. 1.8

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त तथा योजना विभाग  
मंत्रालय  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

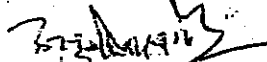
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 27/09/2005

क्रमांक 1/9/2003/वित्त(संग)/घर- भारत के संविधान के अनुच्छेद 243- प्र (1) के खण्ड (ग) तथा अनुच्छेद 243- प्र (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, पंचायती तथा नगरपालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में, उक्त अनुच्छेदों के खण्ड (क) तथा (ख) के अर्थात् सिफारिशों के बारे में एतद्वारा निम्नलिखित निर्देशों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों हेतु निर्दिष्ट करते हैं, अर्थात् :-

1. (एक) यह उद्देश्य कि न केवल एक ओर राज्य सरकार और दूसरी ओर पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों को राजस्व लेखों में प्राप्ति और व्यय का संतुलन बनाया जाए किन्तु साथ ही यह भी कि पूर्वी विभाजन के अधिशेष प्राप्त किया जाए और वित्तीय घाटा कम किया जाए;
  - (दो) राज्य सरकार के स्त्रोत और उन पर भारों, विधिवत, सिविल प्रशासन, पुलिस और न्यायिक प्रशासन, आदि सेवा पर होने वाला व्यय तथा अन्य प्रतिबद्ध व्यय सा दायित्व;
  - (तीन) पूर्वी आदिश्यों का अनुक्षण और रस-स्वास्थ्य तथा दिनांक 31-3-2005 तक पूरी की जाने वाली संस्थाओं पर अनुक्षण व्यय तथा वे मान (मान) जिनके आधार पर पूर्वी आदिश्यों के अनुक्षण के लिए विनिर्दिष्ट रकमों की सिफारिश की गई है और ऐसे व्यय के अनुक्षण (गारंटींग) की शक्ति;
  - (चार) वर्ष 2004-05 में संसाधन के स्तर के अभाव पर 1 अप्रैल 2005 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्षों के लिए राज्य और राज्य सरकार के तथा दूसरी ओर पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के राजस्व लेखों को संतुलित और अतिरिक्त स्क्रैप छूटाने के लिए निर्धारित लक्ष्य और अतिरिक्त कार बढाने की संभावना;
  - (पांच) दक्षता के सुसंयत बेहतर वित्तीय प्रबंध की संभावना और व्यय की निरूपणता;
  - (छ) सामाजिक संस्थानों के अनुक्षण में राज्य सरकार द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं को अतिरिक्त भिरी भूयें कृत्यों और सेवाओं की तुलना में उन कृत्यों और सेवाओं में लगे हुए कर्मचारियों की संख्या का अंतरण;
  - (सात) ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए बाह्य वित्त आयोग की सिफारिश;
2. (एक) पूर्व में स्वीये गये दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार, पंचायतों और नगरपालिकाओं के राजस्व लेखों की प्राप्ति और व्ययों का निर्धारण करते समय, प्राथमिक दृष्टिकोण अपनाना;
  - (दो) संसाधन की बेहतर गतिशीलता और वित्तीय अनुशासन के लिए साथ ही साथ व्यय और राजस्व बढ़ती के विनिश्चयों को निकट से जोड़ने के लिए यथोचित प्रोत्साहन देने की आवश्यकता का सम्यक ध्यान रखना;
  - (तीन) सरकारी कार्यक्रमों के लिए वितरण प्रणाली में तेजी, दक्षता और प्रभावशीलता की आवश्यकता पर विचार करना;
3. आयोग, पूर्वोक्त प्रत्येक विषय पर 1 अप्रैल 2005 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्षों की कालावधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2006 तक उपलब्ध करायेगा, आयोग उस अक्षर को उपदर्शित करेगा, जिस पर वह अपने निष्कर्षों पर पहुँचा है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा कादेशानुसार,

  
(ए.डी. विजयवर्गीय)  
अवर मूल्यांकक